• स्लिरेश चंद और अन्य ***बनाम*** पंचायत निदेशक, हरियाणा
और एक और (के एस तिवाना, जे।

डीएस तेवतिया और कुलवंत सिंह टिवाना से पहले जेजे.

सुरेश चंद और अन्य, याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा के पंचायत निदेशक और एक अन्य -

उत्तरदाता।

सिविल रिट सं. 1978 *का* 3084

22 नवंबर, 1978।

पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम (1953 का IV) द्वारा यथा संशोधित पंजाब ग्राम पंचायत (हरियाणा संशोधन) अधिनियम *(1976 का III) - धारा 100 (2), 102 (1) और (1A)* - भारत का संविधान, *1950* - अनुच्छेद *226* - एक गांव के निवासियों और ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य द्वारा सरपंच के खिलाफ की गई शिकायतें - सरपंच *धारा 102 (1) के तहत निलंबितऐसी शिकायतों पर - ऐसे सरपंच को बाद में बहाल किया गया - बहाली के आदेश को चुनौती देने वाली शिकायतें* - शिकायतकर्ता - क्या रिट *याचिका दायर करने का अधिकार* है - 3 अनुच्छेद *226* में प्रयुक्त 'चोट' और 'न्याय की पर्याप्त विफलता' - *धारा* 102 (1) *के तहत सरपंच को निलंबित करने या बहाल करने का आदेश - धारा* 100(2) के अधीन अर्ध-न्यायिक उपाय की प्रकृति - क्या अनुच्छेद *226 (3) के* तहत रिट याचिका पर रोक लगाने के लिए एक वैकल्पिक उपाय है।

यह माना गया कि ग्राम पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता करने वाले सरपंच को कुछ ऐसे निर्णय लेने होते हैं जो प्रशासनिक होते हैं।

साथ ही न्यायिक भी। उन्हें ग्राम पंचायत के वित्त को संभालना है जो कुछ मामलों में काफी बड़ी राशि है। उसे ग्राम पंचायत की भूमि को पट्टे पर देना है, उसकी संपत्ति का प्रबंधन करना है और समग्र रूप से ग्राम पंचायत के हितों की देखभाल करनी है। इसके अलावा, उन्हें कई अन्य कार्य करने होते हैं और जिस पद के लिए उन्हें चुना गया है, उन्हें खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश करना है, जिसके साथ कोई संदेह, चरित्र का दोष या नैतिक अधमता या ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके द्वारा वह सरपंच

के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय शर्मिंदा महसूस कर सके। प्रत्येक करदाता और इस ग्राम निकाय के लिए चुने गए प्रत्येक सदस्य को यह देखने का अधिकार है कि सरपंच ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके खिलाफ ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 की धारा 102 (1) में उल्लिखित आचरण को उसमें उल्लिखित परिणामों के साथ जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यह लोकतंत्र की उन्नति के अनुरूप है कि जनमत को लोकतांत्रिक संस्थानों के उचित कामकाज पर जांच करनी चाहिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लोगों की नैतिक नैतिकता के बारे में मजबूत धारणाएं हैं। जहां एक सरपंच को गांव के निवासियों और ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों से प्राप्त शिकायतों पर निलंबित कर दिया जाता है और उसके बाद उसे बहाल कर दिया जाता है, शिकायतकर्ता उसकी बहाली पर सवाल उठाने के लिए सरपंच के खिलाफ याचिका बनाए रख सकते हैं। पंचायत का एक निर्वाचित सदस्य उस पद को धारण करने के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाकर सरपंच के रूप में कार्य करने की उम्मीद कर सकता है। निलंबन के कारण, उसके पास उस मौके की तलाश करने का अधिकार आ जाता है जिसे रिमोट नहीं कहा जा सकता है। कानून और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उचित सहारा के बिना एक आदेश पारित करके उस अधिकार से इनकार या इनकार, एक चोट जो पर्याप्त प्रकृति की है, उसके अधिकारों के कारण होती है और वह एक रिट याचिका बनाए रख सकता है।

(पैरा 7 और 8)।

माना जाता है, कि "पर्याप्त चोट" शब्द एक सापेक्ष शब्द है और प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में व्याख्या की जानी चाहिए। 'चोट' शब्द की व्याख्या के लिए कोई कठोर और तेज़ नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसी तरह, भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 (1) के खंड (सी) में प्रयुक्त शब्द 'न्याय की पर्याप्त विफलता' भी एक सापेक्ष शब्द है। कोई भी आदेश जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है या उस क़ानून के अनुरूप नहीं है जिसके तहत इसे पारित किया गया है, दी गई परिस्थितियों में किसी व्यक्ति के लिए न्याय की पर्याप्त विफलता के बराबर हो सकता है। (पैरा 8)।

धारा 102 (1 ए) की भाषा से यह स्पष्ट है कि जांच के दौरान निलंबन के लिए निलंबन से पहले पंच को नोटिस की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन धारा 102 (1) के तहत निलंबन के मामले में यह स्थिति नहीं है। जब किसी पंच के खिलाफ किसी आपराधिक अपराध के लिए जांच, पूछताछ या मुकदमे के लंबित होने के बारे में निदेशक के ध्यान में कोई सूचना लाई जाती है, तो आदेश स्वचालित

• स्लिरेश चंद और अन्य ***बनाम*** पंचायत निदेशक, हरियाणा
और एक और (के एस तिवाना, जे।

रूप से उस प्राधिकारी से नहीं आना चाहिए। उसे आरोप और आरोप की प्रकृति पर अपना दिमाग लगाना है और फिर आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा (1979)2

खुद को संतुष्ट करें कि क्या यह एक प्रकार का है जो उस आरोप के आरोपी व्यक्ति को पंच के रूप में अपने कार्यों के निर्वहन में शर्मिंदा कर सकता है या इसमें नैतिक अधमता या चरित्र का दोष शामिल है। दिमाग लगाकर निलंबन के पक्ष में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, निदेशक को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा और निलंबन के ऐसे आदेश से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने वाले व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस देना होगा। धारा 102 (1) का बारीकी से अध्ययन करने से इस प्रावधान को लागू करने में विधायिका के इरादे के बारे में जानकारी मिलती है। अधिनियम की धारा 102 (1) के तहत कार्य करने वाले निदेशक के आदेश की प्रकृति और इस तरह की वस्तुनिष्ठ संतुष्टि के बाद पंच के निलंबन के पक्ष में निर्णय लेना न केवल कार्यकारी रहता है, बल्कि अर्ध-न्यायिक हो जाता है। क़ानून की भाषा निदेशक को इस विशेष तरीके से कार्य करने के लिए कहती है जो धारा 102 (1 ए) से काफी अलग है। अधिनियम की धारा 102 (1) के तहत एक पंच के निलंबन के बारे में निर्णय लेने का मन बनाने वाले निदेशक के पास इस मामले में एक अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण की आवश्यकताएं हैं और ऐसे प्राधिकरण के कुछ अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त विशेषताओं को संतुष्ट करता है। पंच के निलंबन का आदेश या बहाली का आदेश अर्ध-न्यायिक प्रकृति का होता है। अधिनियम में इन आदेशों के विरुद्ध कोई अपील या संशोधन का प्रावधान नहीं है। चूंकि निलंबन या बहाली का आदेश कार्यकारी आदेशों की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए अधिनियम की धारा 100 (2) आवेदन के लिए आकर्षित नहीं होती है और कोई वैकल्पिक उपाय नहीं है जिसका प्रभावी रूप से पालन किया जा सके ताकि अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका पर रोक लगाई जा सके। मैं (पैरा 10 और 11)।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका *में प्रार्थना की* गई है कि: –

(अ) आक्षेपित आदेश अनुलग्नक पी को निरस्त करते हुए प्रमाण पत्र की प्रकृति में एक

*रिट पारित की जाए।*3 *और उत्तरदाता संख्या*3 *का सह-विकल्प।*3 *ग्राम पंचायत पिपली खेड़ा में।*

(आ) कोई अन्य अप्रामाणिक रिट, आदेश या निर्देश जो इस माननीय न्यायालय के अधिकारी को मामले की परिस्थितियों में उचित और उचित लगता है, जारी किया जाए।

*(इ) अनुबंध पी की प्रमाणित प्रति दाखिल करना।*1 *को हटाया जा सकता है।*

1

(ई) सीएडब्ल्यू का पूरा रिकॉर्ड मांगा जा सकता है।

(उ) प्रतिवादियों को प्रस्ताव की सूचना प्रदान करने की सेवा को कृपया समाप्त किया जाए।

*आगे यह प्रार्थना की जाती है कि इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, आक्षेपित आदेश अनुलग्नक पी का संचालन किया जाए।*3 *पर रोक लगा ई जाए और उत्तरदाता संख्या।*
3 *ग्राम पंचायत पिपली खेड़ा की कार्यवाही में भाग लेने से रोका जाए।*

याचिकाकर्ताओं की ओर *से अधिवक्ता भूप सिंह।*

उत्तरदाता संख्या 10 के लिए *एएस नेहरा, अतिरिक्त एजी हरियाणा।* 1.

प्रतिवादी 2 और 3 *के लिए* बलवंत सिंह मलिक, वकील।

निर्णय *के. एस. तिवाना, जे.*

(एक) सुरेश चंद, धन सिंह और श्रीमती जानकी देवी याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत हरियाणा के पंचायत निदेशक, वेद प्रकाश, ग्राम पंचायत के सरपंच, पिपली खेड़ा और श्रीमती धापो के खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1, 2 और 3 के खिलाफ यह याचिका दायर

• स्लिरेश चंद और अन्य ***बनाम*** पंचायत निदेशक, हरियाणा
और एक और (के एस तिवाना, जे।

की। प्रतिवादी नंबर 2 की बहाली और पंचायत के सदस्य के रूप में प्रतिवादी नंबर 3 के सह-विकल्प को चुनौती देना।

(दो) याचिकाकर्ताओं द्वारा स्थापित मामला यह है कि वेद प्रकाश प्रतिवादी नंबर 2, पिछले कार्यकाल में गांव पिपली खेड़ा की ग्राम पंचायत के सरपंच थे। प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 420 के तहत 13 फरवरी, 1973 को पुलिस स्टेशन, सोनीपत में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 59 के तहत मामला दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ता नंबर 2 ने प्रतिवादी नंबर 1 को इस आशय का आवेदन दिया कि प्रतिवादी नंबर 2 भारतीय दंड संहिता की धारा 406/420 के तहत एक मामले में शामिल था, जिसमें नैतिक पतन शामिल था और इस तरह यह उसे सरपंच के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में शर्मिंदा करेगा। उस आवेदन में, प्रतिवादी नंबर 2 के निलंबन के लिए एक प्रार्थना की गई थी। प्रतिवादी संख्या 1 ने उस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 की धारा 102 (1) के तहत प्रतिवादी संख्या 2 को निलंबित कर दिया, जिसे बाद में अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया - दिनांक 6 जनवरी, 1976 के आदेशों (अनुबंध पी 1) के माध्यम से, यह कहते हुए कि अपराध से उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में शर्मिंदा होने की संभावना थी और इसमें नैतिक अधमता शामिल थी। निलंबन आदेशों के आधार पर, प्रतिवादी नंबर 2 को गांव पिपली खेड़ा की पंचायत के किसी भी कार्य या कार्यवाही में भाग लेने से रोक दिया गया था। निलंबन जारी रहने के दौरान, जून, 1978 में पंचायत चुनाव हुए और प्रतिवादी नंबर 2 को फिर से सरपंच के रूप में चुना गया। याचिकाकर्ता नंबर 1 * जो पंचायत का निर्वाचित सदस्य है,

नए चुनाव ने प्रतिवादी नंबर 2 के खिलाफ उसी आधार पर प्रतिवादी नंबर 1 के समक्ष उनके निलंबन के लिए एक आवेदन दायर किया। पुन: - दिनांक 3 जून, 1958 के आदेशों (अनुलग्नक 1.2) के तहत प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 को सरपंच और पंच के कार्यालय से इस आधार पर निलंबित कर दिया कि इस अपराध से उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में शर्मिंदा होने की संभावना है और इसमें नैतिक अधमता शामिल है और उसे निलंबन की अवधि के दौरान गांव पिपली खेड़ा की पंचायत के किसी भी कार्य या कार्यवाही में भाग लेने से रोक दिया गया है। दिनांक 18 जुलाई, 1978 के आदेशों (अनुबंध पी.3) के तहत, प्रतिवादी नंबर 1 ने प्रतिवादी नंबर 2 को गांव पिपली खेड़ा के सरपंच के रूप में बहाल करते हुए कहा कि प्रतिवादी नंबर 2 के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले से सरपंच के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उन्हें शर्मिंदा होने की संभावना नहीं है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है

कि प्रतिवादी नंबर 2, जो एक प्रभावशाली व्यक्ति है, ने 17 जुलाई, 1978 को हरियाणा के मुख्यमंत्री के समक्ष एक आवेदन दायर किया और अपने प्रभाव के कारण अपनी बहाली के आदेश पारित करने में कामयाब रहे। ये आदेश प्रतिवादी संख्या 3 को ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में सह-चयन करने की दृष्टि से प्राप्त किए गए थे। बहाली के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह दुर्भावनापूर्ण तरीके से पारित एक गैर-भाषी आदेश है , जो शिकायतकर्ता ओं के नोटिस के बिना और प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से दिमाग के बिना प्रतिवादी नंबर 3 के सह-विकल्प को सुविधाजनक बनाने के लिए है।

(तीन) बहाली का आदेश प्रतिवादी नंबर 1, पंचायत निदेशक की ओर से इस आधार पर दिया गया था कि यह किसी के कहने पर नहीं बल्कि प्रतिवादी नंबर 2 की सुनवाई पर पारित किया गया था।

प्रतिवादी संख्या 2 और 3 ने अपने लिखित बयानों में प्रारंभिक आपत्तियां उठाईं कि उपलब्ध ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 100 (2) के तहत संशोधन के माध्यम से वैकल्पिक उपाय के सामने, याचिका सक्षम नहीं थी और याचिकाकर्ताओं को कोई महत्वपूर्ण चोट नहीं थी और न ही न्याय की कोई विफलता थी। निलंबन और बहाली विवादित नहीं थी और इसका कार्य *बदनीयती* जैसा कि आरोप लगाया गया था। }

(चार) याचिकाकर्ताओं के वकील ने पंचायत के सदस्य के रूप में श्रीमती धापो, प्रतिवादी संख्या 3 के सह-विकल्प के खिलाफ चुनौती पर जोर नहीं दिया।

(पाँच) श्री बी.एस.आई मलिक, जो प्रतिवादी संख्या d2 के लिए विद्वान सलाहकार > दो प्रारंभिक आपत्तियां उठाईं: (1) कि याचिकाकर्ताओं का कोई अधिकार नहीं है

(2) यह कि याचिकाकर्ताओं को अधिनियम की धारा 100 (2) के तहत सरकार से संपर्क करने के लिए उपलब्ध वैकल्पिक उपाय के सामने, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के खंड (3) द्वारा बनाई गई रोक के कारण रिट दायर नहीं की जा सकती है।

(छः) प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान *वकील की आपत्ति यह है कि प्रतिवादी* नंबर 2 को सरपंच के रूप में बहाल करने के आदेश अनुलग्नक पी 3 पारित करके, याचिकाकर्ता नंबर 1 और 2

के किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है और उन्हें कोई महत्वपूर्ण चोट नहीं पहुंचाई गई है; न ही आदेश अनुलग्नक पी 3 के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ताओं को कोई महत्वपूर्ण नुकसान हुआ है। श्री मलिक के अनुसार, याचिकाकर्ताओं में से कोई भी सरपंच नहीं है और न ही वे किसी भी अधिकार के उल्लंघन का दावा करने के लिए पान-चायत का प्रतिनिधित्व करते हैं। अधिक से अधिक, उन्हें निलंबन के दो आदेशों, अनुबंध पी. 1 और पी. 2 के पारित होने के लिए अग्रणी जानकारी के आपूर्तिकर्ता कहा जा सकता है। कोई नागरिक अधिकार प्रवाह नहीं है, जिसे बहाली आदेश द्वारा उल्लंघन कहा जा सकता है और याचिकाकर्ता, जो प्रतिवादी नंबर 2 के साथ अपने तनावपूर्ण संबंधों के कारण प्रेरित हैं, उन्हें कोई चोट या क्षति नहीं हुई है। श्री मलिक ने आगे आग्रह किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के खंड (बी) और (सी) में क्रमशः "पर्याप्त चोट" और "न्याय की पर्याप्त विफलता" शब्दों का एक अर्थ है जिसे मामले के परिसर में सख्ती से माना जाना चाहिए। जब तक ये दो तत्व मौजूद नहीं पाए जाते हैं, तब तक याचिकाकर्ता अपने असाधारण रिट अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए इस अदालत से संपर्क नहीं कर सकते हैं। उन्होंने *भारत सरकार और अन्य मुद्दों पर समर्थन मांगा* है। *नेशनल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता* (1)।

(सात) प्रतिवादी नंबर 2 अपने गांव की ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में एक निर्वाचित कार्यालय धारण कर रहा है, जो एक कार्यकारी निकाय है। याचिकाकर्ता पिपली खेड़ा गांव के निवासी हैं और हाउस टैक्स, चूल्हा टैक्स आदि जैसे करों का भुगतान करते हैं, जो ग्राम पंचायत द्वारा लगाए जाते हैं। इसके अलावा, याचिकाकर्ता नंबर 1 उसी ग्राम पंचायत का निर्वाचित सदस्य है, जिसमें प्रतिवादी नंबर 2 सरपंच है। ग्राम पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता करने वाले सरपंच को कुछ निर्णय लेने होते हैं, जो प्रशासनिक और न्यायिक होते हैं। उन्हें ग्राम पंचायतों के वित्त को संभालना है, जो कुछ मामलों में काफी बड़ी राशि है। उसे ग्राम पंचायत की भूमि को पट्टे पर देना है, उसका प्रबंधन करना है।

(1) एआईआर 1977 आंध्र प्रदेश 250।

संपत्ति और समग्र रूप से ग्राम पंचायत के हित को देखें। इसके अलावा, उन्हें कई अन्य कार्य करने होते हैं, जिन्हें यहां याद करना संभव नहीं है। जिस पद के लिए वह निर्वाचित हुए हैं, उस पद पर रहते हुए, उन्हें खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश करना है, जिसके साथ कोई संदेह, चरित्र का दोष या नैतिक अधमता या ऐसी कोई चीज नहीं जुड़ी है, जिसके द्वारा वह सरपंच के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए शर्मिंदा महसूस कर सके। प्रत्येक करदाता और इस ग्राम निकाय के लिए चुने गए प्रत्येक सदस्य को यह देखने का अधिकार है कि सरपंच ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में अधिनियम की धारा 102 (1) में उल्लिखित प्रकार की कोई भी चीज संलग्न है। अधिनियम की धारा 102 (1), जिसे इस फैसले में बाद के चरण में पुन: प्रस्तुत किया जाएगा, को पहली बार जोड़ा गया था जब अधिनियम को 1976 में संशोधित किया गया था। वे सभी व्यक्ति जिनसे ग्राम पंचायत के खजाने में कर आते हैं, और सदस्य इसके प्रबंध निकाय के चुनाव के कारण यह देखने का अधिकार रखते हैं कि सरपंच वह व्यक्ति नहीं है जिसके खिलाफ अधिनियम की धारा 102 (1) में उल्लिखित आचरण को उसमें उल्लिखित परिणामों के साथ जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यह लोकतंत्र की उन्नति के अनुरूप है कि जनमत को लोकतांत्रिक संस्थानों के उचित कामकाज पर जांच करनी चाहिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां लोगों की नैतिक नैतिकता के बारे में मजबूत धारणाएं हैं। प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान वकील श्री बी. एस. मलिक द्वारा की गई आपत्तियों के आधार पर, कानून के अनुरूप आदेशों के परिणामस्वरूप ऐसी संस्थाओं की अनियमितताओं या खराब कामकाज को इन अतितकनीकी आपत्तियों पर हस्तक्षेप से इनकार करके कायम नहीं रखा जा सकता *है।* लोगों को निवारण देने के उद्देश्य से संविधान की शुरूआत के बाद इस देश में रिट क्षेत्राधिकार का दायरा काफी व्यापक हो गया है।

(आठ) चुनाव के बाद, प्रतिवादी संख्या 2 नंबर 2 को याचिकाकर्ता नंबर 1 की शिकायत पर 30 जून, 1978 को सरपंच के कार्यालय से निलंबित कर दिया गया था *और यह आदेश 5 जुलाई, 1978 को प्रतिवादी नंबर 1 के कार्यालय से* सूचना के लिए भेजा गया था। निलंबन के बाद उन्हें बहाल कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में, शिकायतकर्ता होने के नाते याचिकाकर्ता नंबर 1 बहाली पर सवाल उठाने के लिए ^ प्रतिवादी नंबर 2 के खिलाफ याचिका बनाए रख सकता है। इस दृष्टिकोण के लिए समर्थन *मांगे राम* वी *से लिया गया है।हरियाणा राज्य और अन्य* (2)। उस मामले के तथ्य यह थे कि श्री राजिंदर सिंह, प्रतिवादी नंबर 3, पंचायत समिति, गन्नौर ब्लॉक, जिला रोहतक के अध्यक्ष थे। गंभीर अनियमितताओं की शिकायत पर

• स्लिरेश चंद और अन्य ***बनाम*** पंचायत निदेशक, हरियाणा
और एक और (के एस तिवाना, जे।
(2) 1968 पी.एल.आर.

समिति के अधिकांश सदस्यों राजिंदर सिंह को निलंबित कर दिया गया था। उन्होंने अपने निलंबन को एक रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी, जिसे इस आधार पर वापस ले लिया गया कि निलंबन का आदेश संबंधित अधिकारियों द्वारा वापस ले लिया गया था। मांगे राम ने एक रिट याचिका के माध्यम से इस न्यायालय में बहाली के आदेश को चुनौती दी, जहां प्रारंभिक आपत्ति के माध्यम से रिट याचिका दायर करने के उनके अधिकार पर सवाल उठाया गया था। उस मामले में यह निम्नानुसार देखा गया था :-

> "इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समिति के सदस्य के रूप में याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी नंबर 3, उसके अध्यक्ष के कदाचार के खिलाफ शिकायत की थी, और जिसके परिणामस्वरूप उसे निलंबित कर दिया गया था, याचिकाकर्ता ने एक रिट याचिका पेश करते हुए प्रार्थना की कि प्रतिवादी नंबर 3 को निलंबित करने का आदेश गलती से वापस ले लिया गया था, इसे कोई कानूनी अधिकार नहीं कहा जा सकता है या वह बिना किसी अधिकार के है /इसलिए प्रतिवादी नंबर 3 की ओर से उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति को खारिज किया जाता है।

निलंबन के परिणामस्वरूप, सरपंच का पद 5 जुलाई, 1978 के बाद खाली हो गया, जब आदेश अनुलग्नक पी 2 को प्रतिवादी नंबर 2 और विभाग के अन्य संबंधित अधिकारियों को सूचित किया गया था। याचिकाकर्ता नंबर 1, जो पंचायत का निर्वाचित सदस्य है, उस पद को धारण करने के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाकर सरपंच के रूप में कार्य करने की उम्मीद कर सकता है। निलंबन के कारण, उन्हें उस मौके की प्रतीक्षा करने का अधिकार दिया गया था, जिसे दूरस्थ नहीं कहा जा सकता है। कानून और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उचित सहारा लिए बिना अनुलग्नक पी. 3 का आदेश पारित करके उस अधिकार से इनकार या इनकार करना, एक चोट जो पर्याप्त प्रकृति की है, उसके अधिकारों के लिए

हुई है। *भारत सरकार और अन्य राष्ट्रीय* तंबाकू कंपनी। *भारतीय सरकार लिमिटेड, कलकत्ता* (सुप्रा), जिसने मुख्य रूप से संविधान (42 संशोधन) अधिनियम की धारा 58 के आयाम और दायरे से संबंधित निर्णय दिया, ने आम तौर पर इस प्रश्न का समाधान किया है। निर्णय के पैरा 14 में, पूर्ण पीठ के विद्वान न्यायाधीशों ने टिप्पणी की: –

> "'पर्याप्त प्रकृति की चोट' क्या है और 'न्याय की पर्याप्त विफलता' क्या है, इस पर सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा उनके समक्ष रखी गई शिकायतों के संदर्भ में कई मामलों में विचार किया गया है। क्या कोई गंभीर चोट लगी थी या न्याय की पर्याप्त विफलता थी, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर तय किया जाएगा। इन अभिव्यक्तियों को परिभाषित करना न तो संभव है और न ही वांछनीय है।

निर्णय के पैरा 15 में, विद्वान न्यायाधीशों ने एक उदाहरण देकर चोट के दायरे पर चर्चा की कि एक छोटी सी घटना के परिणामस्वरूप समाज के निचले तबके के व्यक्ति को चोट लग सकती है, जो समाज में उच्च पद से संबंधित व्यक्ति के मामले में बहुत छोटी प्रतीत हो सकती है और आसानी से अनदेखा किया जा सकता है, लेकिन यह पूर्व वर्ग के आदमी के लिए एक बड़ी चोट हो सकती है। यहां तक कि इस मामले के सादृश्य पर, 'पर्याप्त चोट' शब्द, एक सापेक्ष शब्द है और प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में व्याख्या की जानी है। 'चोट' शब्द की व्याख्या के लिए कोई कठोर और तेज़ नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसी तरह, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 (1) के खंड (सी) में प्रयुक्त शब्द, 'न्याय की पर्याप्त विफलता' भी एक सापेक्ष शब्द है। कोई भी आदेश जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है या क़ानून के अनुरूप नहीं है, जिसके तहत इसे पारित किया गया है, दी गई परिस्थितियों में किसी व्यक्ति के लिए न्याय की पर्याप्त विफलता के बराबर हो सकता है। ए.आई.आर. 1977 आंध्र प्रदेश 250 में रिपोर्ट किया गया मामला प्रतिवादी संख्या 2 के वकील को कोई मदद नहीं देता है। फैसले के आने वाले पैरा में, इस पहलू पर चर्चा की जाएगी कि आदेश धारा 102 (1) की भाषा के अनुरूप नहीं है और जिस उद्देश्य के साथ यह प्रावधान पेश किया गया था और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है, उस पर चर्चा की जाएगी। आक्षेपित आदेश अनुलग्नक पी. 3, मेरे विचार में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 (1) के खंड (बी) और (सी) को आकर्षित करता है, और याचिकाकर्ता नंबर 1 को आदेश *से* असंतुष्ट व्यक्ति होने के नाते, रिट पक्ष पर अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए

• स्लिरेश चंद और अन्य ***बनाम*** पंचायत निदेशक, हरियाणा
और एक और (के एस तिवाना, जे।
इस न्यायालय से संपर्क करने का अधिकार है।

(नौ) इस अधिनियम की धारा 100 (2) द्वारा प्रदान किए गए वैकल्पिक उपाय के मद्देनजर याचिका की विचारणीयता के बारे में है। अधिनियम की धारा 100 इस प्रकार है: -

"100 (1) सरकार किसी भी ग्राम पंचायत की कार्यवाही के रिकॉर्ड को बुला सकती है और उसमें पारित किसी कार्यकारी आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से जांच कर सकती है और आदेश की पुष्टि, संशोधन या निरस्तीकरण कर सकती है। (2) सरकार किसी भी समय, ऐसे आदेश की वैधता और औचित्य के रूप में स्वयं को संतुष्ट करने के प्रयोजनों के लिए इस अधिनियम के तहत किए गए किसी कार्यकारी आदेश के रिकॉर्ड की मांग और जांच कर सकती है और ऐसे आदेश की पुष्टि, संशोधन या निरसन कर सकती है।

(दस) अधिनियम की धारा 102, जैसा कि पहले संदर्भित किया गया था, को वर्ष 1976 में संशोधित किया गया था। प्रतिवादी के विद्वान वकील ने अधिनियम की धारा 102 के संशोधन से पहले इस न्यायालय द्वारा तय किए गए मामलों का हवाला देते हुए दिखाया कि पंच को उसके निलंबन से पहले कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं थी और तर्क दिया कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा पारित प्रतिवादी नंबर 2 की बहाली का आदेश केवल एक कार्यकारी आदेश था। जिसे राज्य सरकार द्वारा रिकॉर्ड मांगने और उसकी वैधता और औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट करने के बाद संशोधित या रद्द किया जा सकता है। दूसरी ओर, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि अधिनियम की धारा 102 (1) के तहत पारित आदेश, जैसा कि यह अब है, एक कार्यकारी आदेश नहीं है, बल्कि एक अर्ध-न्यायिक आदेश है, जिसे धारा में उल्लिखित प्राधिकरण को उसके समक्ष रखी गई सामग्री का आकलन करने और धारा 102 में उल्लिखित सामग्री के पक्ष या विपक्ष में सामग्री के अस्तित्व के बारे में निष्पक्ष रूप से संतुष्ट करने के बाद पारित करना होगा। 1) अधिनियम का (संशोधित)। प्रतिद्वंद्वी तर्कों की सराहना करने के लिए, अधिनियम की धारा 102 को पुन: पेश करना उचित होगा जैसा कि यह संशोधन से पहले और संशोधन के बाद था।

1

संशोधन से पहले:-

"102 (1) उपायुक्त जांच के दौरान एक पंच को निलंबित कर सकता है और उसे उस अवधि के दौरान उक्त निकाय के किसी भी कार्य या कार्यवाही में भाग लेने से रोक सकता है और उसे उक्त निकाय के रिकॉर्ड, धन या किसी भी संपत्ति को इस संबंध में अधिकृत व्यक्ति को सौंपने का आदेश दे सकता है।

(दो) * * * *

(तीन) * * * *

(चार) * * * *"

संशोधन के पश्चात :-

(पाँच) 2(1) निदेशक किसी ऐसे पंच को निलंबित कर सकेगा जहां उसके विरुद्ध किसी आपराधिक अपराध के संबंध में कोई मामला विचाराधीन है।

(छः) जांच, पूछताछ या परीक्षण, यदि, निदेशक की राय में, उसके खिलाफ लगाए गए आरोप या कार्यवाही से उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में शर्मिंदा होने की संभावना है या इसमें नैतिक अधमता या चरित्र का दोष शामिल है।

(IA) निदेशक या उपायुक्त जांच के दौरान किसी पंच को किसी भी कारण से निलंबित कर सकते हैं जिसके लिए उसे हटाया जा सकता है।

(अठ्ठारह) इस धारा के तहत निलंबित पंच निलंबन की अवधि के दौरान पंचायत के किसी भी कार्य या कार्यवाही में भाग नहीं लेगा और अपने कब्जे में या अपने नियंत्रण में पंचायत के रिकॉर्ड, धन या किसी अन्य संपत्ति को इस संबंध में उपायुक्त द्वारा अधिकृत व्यक्ति को सौंप देगा।

* * * # *»

धारा 100 (2) केवल तभी लागू होगी जब आदेश कार्यकारी प्रकृति का हो। इसलिए, यह देखना आवश्यक हो जाता है कि क्या कोई आदेश, जैसा कि इस मामले में लागू किया गया है, एक कार्यकारी

• स्लिरेश चंद और अन्य ***बनाम*** पंचायत निदेशक, हरियाणा
और एक और (के एस तिवाना, जे।
है या प्रकृति में अर्ध-न्यायिक है।

धारा 102 (1) (पुराना) के तहत निलंबन धारा 102 (एलए) (नया) के बराबर है। धारा 102 (1ए) को नया जोड़ा गया है। इससे पहले, केवल एक प्रकार का निलंबन होता था जैसा कि धारा 102 (एल) (पुराना) से स्पष्ट है और वह जांच के दौरान था। संशोधन के बाद, निलंबन अब दो प्रकार का है; एक धारा 102 (1) में प्रदान की गई है, जहां एक पंच को उसके खिलाफ जांच, पूछताछ या परीक्षण के तहत आपराधिक अपराध के संबंध में निलंबित किया जा सकता है, यदि लगाए गए आरोप या की गई कार्यवाही से उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है या नैतिक पतन या चरित्र का दोष शामिल है, और दूसरा जांच के दौरान है।

धारा 102 (पुरानी) और धारा 102 (1-ए) की भाषा से यह स्पष्ट है कि जांच के दौरान निलंबन के लिए निलंबन से पहले पंच को नोटिस की आवश्यकता नहीं होती है और यह दृष्टिकोण इस न्यायालय के कई निर्णयों में सुनाया गया है, जिसमें से मेरा संदर्भ *राजिंदर सिंह बनाम राजेंद्र सिंह बनाम राजेंद्र सिंह को दिया जा सकता* है। *पंचायत* निदेशक, *पंजाब, चंडीगढ़* (3), *रत्ती राम* वी. *डिप्टी कमिश्नर, पटियाला* (4) और *गुरदयाल सिंह* वी. *पंजाब राज्य आदि।* (5) लेकिन, यह नहीं है

(तीन) *T963~ P "L.R.L 1085?"
(चार) 1965 पी.एल.आर.
(पाँच) 1971 पी.एल.जे.

धारा 102 (1) (नया) के तहत निलंबन के मामले में स्थिति। जब किसी पंच के खिलाफ किसी आपराधिक अपराध के लिए जांच, पूछताछ या विचारण के लंबित होने के बारे में निदेशक के ध्यान में कोई सूचना लाई जाती है, तो आदेश स्वचालित रूप से उस प्राधिकारी से नहीं आना चाहिए। उसे आरोप और आरोप की प्रकृति पर अपना दिमाग लगाना है और फिर खुद को संतुष्ट करना है कि क्या यह एक प्रकार का है, जो उस आरोप के आरोपी व्यक्ति को पंच के रूप में अपने कार्यों के निर्वहन में शर्मिंदा कर सकता है या इसमें नैतिक अधमता या चरित्र का दोष शामिल है। जांच, पूछताछ या परीक्षण के तहत सभी आपराधिक अपराध किसी को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में शर्मिंदा नहीं कर सकते हैं या इसमें नैतिक कष्ट या चरित्र का दोष शामिल नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए भारतीय दंड संहिता

की धारा 304-ए, 323, 326 आदि के तहत एक आरोप लें। इनसे धारा 102 (1) में उल्लिखित किसी भी पंच को कोई समस्या नहीं हो सकती है। ये संपूर्ण नहीं हैं और केवल चित्रण के उद्देश्य से दिए गए हैं। नैतिक अधमता से जुड़ा अपराध संभवतः प्रत्येक मामले में धारा 102 (1), (नया) में परिकल्पित प्रकृति की शर्मिंदगी का कारण बन सकता है, लेकिन शर्मिंदगी पैदा करने वाले सभी अपराधों में नैतिक अधमता शामिल नहीं हो सकती है। प्राधिकरण को किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उसके समक्ष रखी गई सामग्री का गंभीर रूप से विश्लेषण करना होगा और धारा 102 (1) (नए) के सभी तीन अवयवों पर स्पष्ट रूप से विचार करना होगा। निदेशक को खुद को संतुष्ट करना होगा कि *प्रथम दृष्टया* चीजें मौजूद हैं, जो निलंबन की कार्रवाई की मांग कर सकती हैं या उसके द्वारा ऐसी कार्रवाई का आह्वान नहीं कर सकती हैं। वह इस निष्कर्ष पर तभी पहुंच सकता है जब वह अपने चेतन मन को लागू करता है और निष्पक्ष रूप से संतुष्ट होता है। यदि इस तरह के विचार के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि *पंच के निलंबन के लिए प्रथम दृष्टया* कोई मामला नहीं है , तो वह उसे निलंबित नहीं कर सकता है। दूसरी ओर, यदि उसकी वस्तुनिष्ठ संतुष्टि इस आशय की है कि जांच, पूछताछ या परीक्षण के तहत अपराध की प्रकृति से उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में शर्मिंदा होने की संभावना है या इसमें नैतिक अधमता या चरित्र का दोष शामिल है, तो धारा 102 (एल) (नए) में 'हो सकता है' शब्द में 'इच्छा' का बाध्यकारी बल है और उसके पास शिकायत किए गए व्यक्ति को निलंबित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। निदेशक चीजों को सीखने या किसी के द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर स्वत: कार्रवाई कर सकता है। कुछ मामलों में, प्रदान की गई जानकारी स्व-निहित हो सकती है और इसके आधार पर निदेशक एक सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। ऐसे मामले नहीं हो सकते हैं जब जानकारी अधूरी हो सकती है और निदेशक को मामले में आगे की जांच की आवश्यकता महसूस हो सकती है, जिसके लिए उन्हें शिकायतकर्ता की सहायता की आवश्यकता हो सकती है। उस स्थिति में उसे सूचना प्रदान करने वाले व्यक्ति को सुनना होगा। इसमें निलंबन का आदेश पारित करने से पहले शिकायतकर्ता की सुनवाई की परिकल्पना की गई है। मन का ऐसा अनुप्रयोग नहीं है कार्यकारी आदेश की विशेषता। धारा 102 (1) (नया) की आवश्यकता के रूप में मन का ऐसा प्रयोग धारा 102 (1-ए) या धारा 102 (1)

• स्लिरेश चंद और अन्य ***बनाम*** पंचायत निदेशक, हरियाणा
और एक और (के एस तिवाना, जे।

(पुराना) द्वारा नहीं माना जाता है। धारा 102 (1) (नए) के तहत निलंबन के पक्ष में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, ऊपर चर्चा किए गए तरीके से दिमाग लगाकर निदेशक को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा और उस व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस देना होगा, जो निलंबन के ऐसे आदेश से प्रतिकूल रूप से प्रभावित है। यदि उसे अवसर दिया जाए तो वह निदेशक को संतुष्ट कर सकता है कि आरोप या आपराधिक अपराध, जो जांच, पूछताछ या परीक्षण का विषय है, न तो नैतिक पतन या चरित्र का दोष है और न ही किसी भी तरह से पंच के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उसे शर्मिंदा करने की संभावना है। धारा 102 (एल) (नई) का बारीकी से अध्ययन करने से इस प्रावधान को लागू करने में विधायिका के इरादे के बारे में भी जानकारी मिलती है। जहां तक निलंबन का संबंध है, यह पुरानी धारा 102 (1) में मौजूद था। यदि इस तरह के विवेक की आवश्यकता नहीं थी, तो इस भाषा में संशोधन के बाद धारा 102 (1) को अधिनियमित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। संशोधन के पीछे एक उद्देश्य है जो यह है कि उन मामलों में निलंबन स्वचालित या यांत्रिक नहीं होना चाहिए, जहां कोई जांच नहीं है। निदेशक को अपने दिमाग का प्रयोग करना चाहिए और आरोप का वस्तुनिष्ठ अध्ययन करना चाहिए और फिर निर्णय लेना चाहिए। जब यह स्थिति होती है, तो धारा 102 (1) (नए) के तहत कार्य करने वाले निदेशक के आदेश की प्रकृति और इस तरह की वस्तुनिष्ठ संतुष्टि के बाद पंच के निलंबन के पक्ष में निर्णय लेना, केवल कार्यकारी नहीं रहता है, बल्कि अर्ध-न्यायिक हो जाता है। क़ानून की भाषा निदेशक को इस विशेष तरीके से कार्य करने के लिए कहती है, जो धारा 102 (1-ए) के रूप में पुन: अधिनियमित पुराने प्रावधान से काफी अलग है।

(11) थीस्कासी-न्यायिक प्राधिकारी एलसी विशेषताओं की पुष्टि करते हैं जो उन्हें कार्यकारी अधिकारियों से अलग करते हैं। प्राधिकरणों की इस प्रकृति को सांविधिक प्रावधानों से आंका जाना चाहिए, जिसके तहत उसे कार्य करना आवश्यक है। इस तरह के प्राधिकरण की कुछ विशेषताएं यह हैं कि जब पार्टियों के बीच कोई मुद्दा उठता है, तो इसे एक प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए और पारित किए जाने वाले आदेश से प्रतिकूल रूप से प्रभावित पार्टियों को नोटिस के बाद सुना जाना है। ऐसे प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश में कारण होने चाहिए। जब पार्टियों के बीच कोई मुद्दा उठता है और दोनों पक्ष अपने पक्ष में आरोप के प्रभाव की व्याख्या का दावा करते हैं, तो प्राधिकरण को आरोप की प्रकृति के प्रभाव का आकलन करने के लिए अपना दिमाग लगाना पड़ता है। किसी दिए गए मामले में इसे अपने निष्कर्षों को आधार बनाने के लिए कुछ सामग्री की

आवश्यकता हो सकती है। अर्ध-न्यायिक निकाय का गठन क्या है, इस संबंध में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों को बॉम्बे *प्रांत बनाम बॉम्बे में दर्ज किया गया है*। *खुशालदास* दक्षिणी। *बोर्ड ऑफ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट एजुकेशन* वी में *एडवम* (6) का पालन किया गया *।घनश्याम दास गुप्ता और अन्य* (7) हैं:

"सिद्धांत, जैसा कि मैं उन्हें समझता हूं: –

(i) यदि कोई संविधि किसी प्राधिकारी, जो सामान्य अर्थों में न्यायालय नहीं है, को यह अधिकार देती है कि वह संविधि के अधीन एक पक्ष द्वारा किए गए दावे से उत्पन्न होने वाले विवादों का निर्णय ले सकता है, जिसके दावे का दूसरे पक्ष द्वारा विरोध किया जाता है और एक-दूसरे का विरोध करने वाले पक्षकारों के संबंधित अधिकारों का निर्धारण किया जा सकता है। और इसके विपरीत क़ानून में कुछ भी नहीं होने की स्थिति में न्यायिक रूप से कार्य करना प्राधिकरण का कर्तव्य है और प्राधिकरण का निर्णय एक अर्ध-न्यायिक कार्य है; और

(ज) यदि किसी सांविधिक प्राधिकारी को ऐसा कोई कार्य करने की शक्ति है जो विषय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा, तो यद्यपि प्राधिकारी के अलावा दो पक्ष नहीं हैं और प्रतियोगिता उस कार्य को करने का प्रस्ताव करने वाले प्राधिकारी और उसका विरोध करने वाले विषय के बीच है, प्राधिकरण का अंतिम निर्धारण अभी तक एक न्यायिक अधिनियम होगा बशर्ते कि प्राधिकारी को न्यायिक रूप से कार्य करने के लिए संविधि द्वारा अपेक्षित हो।

दूसरे शब्दों में, जबकि निर्णय लेने वाले प्राधिकारी के अलावा दो पक्षों की उपस्थिति *प्रथम दृष्टया* और किसी अन्य कारक के अभाव में प्राधिकरण पर न्यायिक रूप से कार्य करने का कर्तव्य थोपेगी, ऐसे दो पक्षों की अनुपस्थिति प्राधिकरण के कार्य को अर्ध-न्यायिक अधिनियम की श्रेणी से बाहर निकालने में निर्णायक नहीं है, यदि प्राधिकरण को न्यायिक रूप से कार्य करने के लिए कानून द्वारा आवश्यक है।

यह मामला ऊपर उद्धृत खुशालदास के मामले (सुप्रा) *में (एफआई) में निहित टिप्पणियों के भीतर आता* है । इस मामले में पक्षों के बीच एक मुद्दा पैदा हो गया है और दोनों पक्ष अपने पक्ष में मुद्दे के प्रभाव का दावा करते हैं और एक ही प्राधिकारी ने अलग-अलग अवसरों पर पेटीज के पक्ष में फैसला

• स्लिरेश चंद और अन्य ***बनाम*** पंचायत निदेशक, हरियाणा
और एक और (के एस तिवाना, जे।
सुनाया है। निदेशक अपनी जिम्मेदारी निभा रहेहैं

(6) ए.आई.आर. 1950 एस.सी. 222.

ए.आई.आर. 1962 एस.सी. 1110.

अधिनियम की धारा 102 (1) के तहत एक पंच के निलंबन के बारे में निर्णय लेने के लिए इस मामले में एक अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण की आवश्यकताएं हैं और ऐसे प्राधिकरण के कुछ अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त विशेषताओं को संतुष्ट करता है। पंच के निलंबन का आदेश या बहाली का आदेश अर्ध-न्यायिक प्रकृति का होता है। अधिनियम में इन आदेशों के विरुद्ध कोई अपील या संशोधन प्रदान नहीं किया गया है जैसा कि राज्य या पंजाब में लागू अधिनियम में है। चूंकि निलंबन या बहाली का आदेश कार्यकारी आदेशों की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए अधिनियम की धारा 100 (2) आवेदन के लिए आकर्षित नहीं होती है और कोई वैकल्पिक उपाय नहीं है, जिसका याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रभावी रूप से पालन किया जा सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका एकमात्र उपाय है जिसका लाभ याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाया जा सकता है।

(बारह) प्रारंभिक आपत्तियों का निर्णय हमें आक्षेपित आदेश के गुण-दोष पर लाता है। 30 जून, 1978 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पारित आदेश अनुलग्नक पी 2 में इन शब्दों में निलंबन के आधार शामिल हैं: "जबकि अपराध से उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में शर्मिंदा होने की संभावना है और इसमें नैतिक अधमता शामिल है"। इन शब्दों से पता चलता है कि निलंबन के लिए प्रतिवादी नंबर 1 की संतुष्टि इन दो आधारों पर आधारित थी, जो कर्तव्यों के निर्वहन और नैतिक पतन की भागीदारी में शर्मिंदगी है। इस आदेश को याद करते हुए, अनुबंध पी. 3 के *माध्यम* से, प्रतिवादी नंबर 1 ने दर्ज किया, "चूंकि श्री वेद प्रकाश के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले से सरपंच के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उन्हें शर्मिंदा होने

की संभावना नहीं है, इसलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाता है"। आदेश अनुबंध पी 3 नैतिक पतन के क्षेत्र को कवर नहीं करता है। प्रतिवादी नंबर 1 ने उस आधार पर निलंबन का आदेश खाली नहीं किया था। इसका मतलब यह होगा कि जांच, पूछताछ या परीक्षण के तहत अपराध के कारण प्रतिवादी नंबर 2 की नैतिक अधमता की भागीदारी अभी भी बनी हुई है। इससे पता चलता है कि प्रतिवादी नंबर 1 ने बहाली आदेश पारित करते समय अपेक्षित ध्यान नहीं दिया था। अनुलग्नक पी. 3 में भी ऐसा कोई कारण नहीं है कि अनुबंध पी. 2 के पारित होने के 18 दिनों के भीतर, प्रतिवादी नंबर 1 एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रतिवादी नंबर 2 के खिलाफ विचाराधीन अपराध उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में शर्मिंदा नहीं करेगा। ऐसे मामलों में, प्राधिकारियों को निष्कर्ष पर पहुंचने का कारण बताना अपेक्षित होता है, जब उनके द्वारा पारित आदेश पूर्व के आदेश के विपरीत होते हैं। इस प्रकार अनुलग्नक पी. 3 इसमें शामिल मामले पर उचित विचार किए बिना इसके पारित होने को दर्शाता है। यह एक गैर-बोलने वाले आदेश का चरित्र है, जिसे अर्ध-न्यायिक अधिकारियों से प्रवाह की उम्मीद नहीं है ^ ऑन

इन आधारों पर इस आदेश को रद्द किए जाने की आवश्यकता है। इस आदेश को रद्द करने को सही ठहराने के लिए एक और आधार है, यानी याचिकाकर्ता नंबर 1 की शिकायत पर प्रतिवादी नंबर 2 इस निष्कर्ष पर पहुंचा था जैसा कि अनुबंध पी 2 में दर्ज किया गया है। जब प्रतिवादी नंबर 1 को इसके पारित होने के तुरंत बाद अनुबंध पी 2 से अलग होना था, तो स्थिति और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और *मांगे राम के मामले* (सुप्रा) में निर्धारित सिद्धांत की अनिवार्यता के लिए आवश्यक था कि याचिकाकर्ता नंबर 1 को प्रस्तावित आदेश के खिलाफ सुना जाना चाहिए था। इसलिए, उपरोक्त कारणों से आदेश अनुलग्नक पी 3 को रद्द किया जाता है।

(तेरह) चूंकि आदेश अनुलग्नक पी 3 को उपरोक्त आधारों पर रद्द कर दिया गया है, इसलिए यह तर्क नहीं उठता कि अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण को आदेश की समीक्षा करने के लिए अधिनियम के तहत शक्ति नहीं दी गई है।

• स्लिरेश चंद और अन्य ***बनाम*** पंचायत निदेशक, हरियाणा
और एक और (के एस तिवाना, जे।

(चौदह) बहस के दौरान, श्री बी.एस.मलिक ने आशंका व्यक्त की कि यदि अनुबंध पी.3 को रद्द कर दिया जाता है, तो प्रतिवादी नंबर 2 इस अदालत में आदेश अनुलग्नक पी. 2 को रद्द करने की मांग करने के लिए आ सकता है, जिसके *तहत* उन्हें निलंबित कर दिया गया था , क्योंकि उन्हें इसके बारे में कोई नोटिस नहीं दिया गया था और न ही इसमें यह दिखाने के लिए कोई सामग्री है कि क्या प्रतिवादी नंबर 1 ने उनके सामने मौजूद सामग्री पर अपना दिमाग लगाया था। इसके गुजरने के समय। अनुलग्नक पी. 2 भी अनुबंध पी. 3 के समान दोष से ग्रस्त है क्योंकि आदेश में उल्लिखित आधारों पर प्रतिवादी नंबर 2 को उसके निलंबन से पहले अवसर नहीं दिया गया था। यद्यपि इस आदेश को रद्द करने के लिए किसी भी पक्ष द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई है, लेकिन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मुकदमेबाजी की बहुलता से बचने के लिए, हम अनुलग्नक पी 2 को भी रद्द करते हैं।

(पंद्रह) अनुलग्नक पी. 2 और पी. 3 के आदेशों को रद्द करने का शुद्ध परिणाम यह है कि प्रतिवादी नंबर 1 अब अधिनियम की धारा 102 (1), (नए) के मद्देनजर प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ याचिकाकर्ता नंबर 1 की शिकायत पर पुनर्विचार करेगा और इस फैसले में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए इस पर फैसला करेगा।

(सोलह) इसलिए, लागत के बारे में बिना किसी आदेश के रिट याचिका को स्वीकार किया जाता है।

एन. के. एस.

अस्वीकरणः

अनुवादित निर्णय केवल वादकर्ता के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह इसे अपनी भाषा में समझ सके और इसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी न्यायिक और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए मान्य होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

हिमानी सागर
प्रशिक्षित न्याय अधिकारी, हरियाणा